

राजस्थान को डीजल और मिट्टी  
के तेल का आवंटन

3958. श्री भांडा भाई :

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावल :

क्या पेट्रोलियम रसायन तथा उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने पिछले तीन महीनों में डीजल तथा मिट्टी का तेल अधिक मात्रा में आवंटित करने के लिए केन्द्रीय सरकार को पत्र लिखा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने अकाल के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को हाल में दिये गये ज्ञापन में अपनी मांग का उल्लेख किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) : अक्टूबर, और नवम्बर, 1980 में, राजस्थान सरकार ने केवल अपने राज्य के लिए हाई स्पीड डीजल तेल के अतिरिक्त आवंटन के लिए अनुरोध किया था ।

(ग) हाई स्पीड डीजल तेल का मासिक आवंटन इस उत्पाद के पिछले वर्ष के तदनुरूपी महीनों के मूल आवंटन से 5 प्रतिशत वृद्धि के आधार पर किया जाता है । राज्य सरकार से प्राप्त अनुरोधों के अनुसार, राजस्थान सरकार का अक्टूबर, और नवम्बर, 1980 और दिसम्बर, 1980 का एच० एस०—डी का आवंटन बढ़ा दिया गया है । जहां तक मिट्टी के तेल का सम्बन्ध है, आवंटन पिछले वर्ष के तदनुरूप महीनों की बिक्री से 5 प्रतिशत वृद्धि के आधार पर किया जाता है ।

Audit Check on Amenities for Employees of Companies

3954. SHRI A. U. AZMI: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5981 on 29th July, 1980 regarding amenities for employees of large Industrial Houses and state:

(a) whether in view of the obligation of the Auditors for being appointed by the Board of Directors who generally dominate the annual general meetings where formally such appointments are approved, they do not generally bring to notice such misuse of Company's vehicles by their Executives labelled as 'Staff cars' and thus evade not only Income-tax on their total remuneration including perks, but also consume petrol without any limit; and

(b) if so, whether Government propose making some deterrent provision to guard against such clandestine grants of perks to the Executives in circumvention of the provisions of Section 217(2-A) of the Cos. Act, 1956; and if not, the reasons?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI P. SHIV SHANKAR): (a) and (b). Government do not have any information regarding the failure, if any, of the Auditors to bring to the notice of the company, the misuse of the company's vehicles by the executives, evasion of Income Tax on managerial remuneration and consumption of petrol without limit. It is the Auditor's duty under Section 227 of the Companies Act, 1956 to certify the truth or otherwise of the particulars given by the company in such matters and other matters which would ultimately be reflected in the Profit and Loss Account. The High Powered Expert Committee has made certain recommendations relating to the amendment of Section 217(2A) of the Companies Act, 1956, in the above connection. The recommendations